कम पैदावार के कारण तीनों जगह से बिजली ले रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि जो बदरपुर और भाखड़ा है इनकी कैपेसिटी जितनी है उसको पूरा चलाने के लिए कोशिश करेंगे ? क्योंकि दिल्ली की जो आबादी बढ़ रही है और हर साल 13 लाख से ज्यादा कंज्यूमर्स बढ़ते हैं, तो इस कमी को मिटाने के लिए सरकार के पास क्या प्रोग्राम है ? और जो बिजली घर कम बिजली पैदा कर रहे हैं विशेषकर बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ, इनमें आप क्या सुधार करने जा रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इन्द्रप्रस्थ, बदरपुर या दूसरे स्टेशन्स के लिए में पहले ही कह चुका हूं कि 500 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की गई है जिससे मौजूदा प्लान्ट्स का मौडर्नाइजेशन और रिवोवेशन हो सके। उस रुपये को तीन साल के अन्दर लगाया जा सकेगा।

कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को किस तरह से बढ़ाया जाये उसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। तो कई एक स्टैप्स उसके लिए गये हैं :

In order to improve capacity utilisation of the existing thermal power plants, a number of measures are being taken, which include, assistance to State Electricity Boards and power Stations to prepare and undertake plant betterment programmes, adoption of preventive maintenance techniques for reducing the outage periods, arranging spare parts from indigenous and foreign sources, arranging requisite quality and quantity of coal with joint sampling of coal at the power stations end, setting up of task forces for achieving early stablisation of the units ; and also arranging visits of roving teams of operation specialists from Central Electricity Authority to monitor operation practices and render advice and arranging foa training of operational and maintenance staff.

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष जी, यह बार-बार सदन में कहा गया है कि 210 मेगावाट क्षमता की जो विद्युत उत्पादन यूनिट बी० एच० ई० एल० द्वारा निर्मित की जा रही हैं इसमें बायलर की डिजाइन डिफक्टिव होने की वजह से, या जो कोयला देश में प्राप्त हो रहा है वह ठीक न होने के कारण यह उतनी उत्पादन क्षमता पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं और इनकी जैनरेशन कैपेसिटी में शिकायत आती है और उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह लोक सभा में बताया था कि एन० टी० पी० सी० के माध्यम से 500 मेगावाट क्षमता की 10 इकाईयां देश में स्थापित की जा रही हैं। तो जो नये जैनेरेटर बी० एच० ई० एल० द्वारा बनाये जा रहे हैं उनके बायलर की डिज़ाइन में संशोधन कर दिए हैं ताकि जो कोयला हमें मिल रहा है उसके अनुसार वह काम कर सके, और क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि नहीं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : डिज़ाइन के जिन डिफेक्ट्स के कारण विद्युत परिषदों को दिक्कतें आईं और जिन की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी एथारिटी ने उनके बारे में बी. एच. ई एल. के साथ बातचीत की है और उन्होंने फैसला किया है कि कोयले की क्वालिटी और उन दिक्कतों को देखते हुए, विद्युत परिषदों को जिनका सामना करना पड़ा है, बी० एच० ई० एल० अपने डिजाइन में वांछित संशोधन करेंगे।

Memorandum by Representatives of Thermal Plants Regarding Poor Quality of Coal

\+

*230. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA :
SHRI M. RAMGOPAL REDDY

Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representatives of thermal plants|National Council of Power Utilities had in a memorandum submitted to the Government in the recent past stated that the quality of coal supplied by Coal India was very poor and that Coal India failed to meet the full requirements of power plants ;

(b) the loss suffered by power plants during the last three years, year-wise, due to receipt of poor quality of coal ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto and measures proposed to be taken to improve the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI DALBIR SINGH) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir.

(b) It is not possible to quantity the loss suffered by power stations exclusively due to inferior quality of coal.

(c) The National Council of Power Utilities which is a non Official association of Electricity Boards/Power Utilities have submitted a memorandum on problems of coal supply to Thermal Power Stations. The memorandum mainly stresses the need to meet the qualitative and quantitative requirements of coal supplies to Power Stations.

The power|sector is the major consumer of coal in India. The despatches of coal to the Power Stations have been increasing every year as indicated below :—

Year	Despatches of coal to power stations including middlings (in m. t.)	% increase over previous year	Demand as assessed by Planning Commission (in m. t.)	% age satisfaction.
1980-81	36 70	+ 5.3	41.0	89.5
1981-82	46.35	+ 26.3	45.5	101.9
1982-83	51.61	+ 11.3	52.0	99.2
1983-84	58.11	+ 12.6	58.50	99.3

Out of the despatches of 58.11 million tonnes in 1983-84, despatches from Coal India Ltd. were 51.56 m.t. which come to 100.8% of the demand of Coal India Ltd. (51.15 m.t.). It may be seen that the demand of the power stations had been more than fully met by CIL.

As regards quality, the complaints relate mainly to supplies of oversized coal and extraneous material alongwith coal. The problem regarding oversize coal and presence of shale and other extraneous material arises because mining and loading in the large open cast mines is done through mechanised means. A number of measures have been taken to improve the quality of coal supplies to the consumers particularly to the power houses. These include.

1. An indepenent . quality control organisation has been set up in each coal company.

2. Installation of CHPs with provision for sizing and screening of coal wherever required. At present 100 mini CHPs and 50 major CHPs are functioning and they handle 47% of the coal produced. By 1986-87, the strength of CHPs will go up to 308 (130 major CHPs and 178 mini CHPs) and the percentage of coal handled by CHPs will go upto 88%.

3. Electricity Boards have been requested to sign agreements with coal companies which would provide inter-alia for joint sampling of coal supplied and payment of bonus|penalty with reference to the quality of coal supplied.

4. The Coal Controller as an independent authority has been given the powers to determine the grades of coal seams in the mines as also of the coal supplied to consumers and for these purposes to take samples and arrange for the testing of coal suomoto or if any complaint is made in this regard by any consumer. The Coal Controller's decision in the matter shall be final.

5. Instructions have been issued to coal companies to maintain quality of coal supplies by controlled blasting and handpicking of shale, stones etc. where CHPs do not exist.

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर जो स्टेटमैंट रखा ...

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : वक्तव्य ।

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : Thank you for giving me a good word.

.....जो वक्तव्य रखा है, उसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है । मैंने पूछा है कि नेशनल कौंसिल आफ़ पावर यूटिलिटीज़ ने जो मेमोरेंडम भेजा है, उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाये हैं । मन्त्री महोदय ने कदम उठाने की बात कही है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि क्या उन कदमों को उठाने के परिणामस्वरूप कोयले के मामले में जो कमियाँ हैं, क्या वे पूरी हो सकेंगी । इस देश में बिजली की कमी है और उसके कारणों में सबसे बड़ा कारण कोयले की क्वालिटी में गिरावट है । यह सवाल अनेक समितियों द्वारा बार-बार उठाया गया है और कहा गया है कि कोयले की कमी और उसकी क्वालिटी के बारे में सरकार कदम उठाए । लेकिन हम देखते हैं कि स्थिति ज्यों की त्यों है । एमिनेंट इन्जीनियर, श्री थाता राव, ने इस मेमोरेंडम में कोयले की सप्लाई के बारे में जो एलिगेशन्ज़ लगाई हैं, वे निश्चित रूप से विचारणीय है । कोयले के साथ सैंकड़ों टन पत्थर, हजारों टन राख, लोहे के कपलिंग्ज और रेलवे का अन्य सामान जाता है, वेमेंट में कमी होती है, जिसके कारण अनेक पावर हाउस डैमेज हो चुके हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं, क्या उसने उनका मूल्यांकन किया है कि उनके परिणामस्वरूप पावर हाउसिज़ में कोयले की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं, अगर नहीं किया है, तो क्या मंत्री महोदय केवल कदम उठाने से ही संतुष्ट हो जायेंगे ।

श्री दलबीर सिंह : एक प्राईवेट आर्गनाइजेशन ने अपने मेमोरेंडम में कोयले की क्वालिटी और सप्लाई के मुताल्लिक जो बातें कही हैं, उनका जवाब इस स्टेटमेंट में दे दिया गया है । क्वालिटी को इम्परुव करने के लिए जो कदम उठाए गये हैं । कोयले की क्वालिटी को सुधारने के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट में पत्थर और दूसरे

एक्ट्रेनियम मैटीरियल को कोयले से अलग करने के अरेंजमेंट्स हैं। अभी तक 47 परसेंट कोल का प्रोडक्शन उसके नीचे आ चुका है और 86-87 तक 88 परसेंट कोल के टोटल प्रोडक्शन का हैंडलिंग प्लान्ट के अन्तर्गत ले जाया जायेगा जिसके अन्दर कोल की क्वालिटी ओटोमेटिकली सुधरती चली जायेगी। यह कहना गलत है कि अभी तक कोल की कोई क्वालिटी नहीं सुधरी। कोल की क्वालिटी में सुधार आया है लेकिन कोल की क्वालिटी के मुताल्लिक यह है कि ज ों ज्यों हम पुरानी खानों के अंदर नीचे जाते हैं और कोयला आगे निकलता जाता है उसकी क्वालिटी आटोमेटिकली डेटरिओरेट होती जाती है और नयी खानों के अंदर भी जहां ओपेन कास्ट माइन्स हैं, उनके अन्दर भी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होने के कारण ऐसा होता है क्योंकि हमारी बेसिकली कोल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। उसके कारण भी वह क्वालिटी खराब होती है। लेकिन कोल हैंडलिंग प्लान्ट के जरिए वह सारा कवर हो जाएगा और जैसा मैंने कहा 86-87 के अंदर 88 परसेंट इसके नीचे आ जाएगा और इसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी।

यह कहना कि सारा का सारा जितना भी जेनरेशन है सिर्फ कोल की क्वालिटी की वजह से उसके प्लांट लोड फैक्टर में कमी आती है, यह बात नहीं है। इसके और बहुत से कारण भी हैं। यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इससे जुड़े हुए दूसरे कारण भी हैं जिनकी वजह से उसका जैनेरेशन कम होता है। अब देखिए कि एक ही क्वालिटी का कोल, जैसे सिंगरौली का कोल ही कोटा में जाता है, उसके अंदर प्लांट लोड फैक्टर 80 परसेंट है और ओवरा के अंदर जाता है, वहां उसका 30 परसेंट प्लांट लोड फैक्टर है। क्वालिटी आफ कोल के ऊपर हो तो उसका भी प्लांट लोड फैक्टर एक ही होना चाहिए। ये डिफरेंट उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि मैंने यह बताने की कोशिश की कि सिर्फ कोल की क्वालिटी और कोल ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके कारण प्लांट लोड फैक्टर इम्प्रूव किना जा सके। और भी कारण हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय शिव शंकर जी इसको रिकंसाइल करें कि सिंगरौली को कोयला कोटा और ओवरा में इतना फर्क क्यों डालता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री शिव शंकर) : बहुत से फैक्टर्स हैं। वहां का बायलर है, जैनेरेटर का डिजाइन है, मैनेजमेंट की कमी और ट्रेनिंग परसोनेल की कमी ये सब चीजें मिलकर इसका कारण बनती हैं। यह नहीं है कि केवल कोल ही कारण है। यह जरूर है कि कोल एक मेजर फैक्टर है।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : मंत्री जी ने जवाब देने की कोशिश तो की है लेकिन मुझे स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला। मैंने स्वयं यह कहा है कि बिजली के उत्पादन में कमी के कारणों में और चीजों के अलावा कोयला भी एक बड़ा कारण है और आपने भी तथ्यों से इस बात को स्वीकार किया सिंगरोली का उदाहरण देकर और कोटा और ओवरा का उदाहरण देकर कि पावर हाउसेस में इनएफिश्येंसी है, उसकी बर्किंग ठीक नहीं है इसलिए एक जगह उसी कोयले से प्लान्ट लोड फैक्टर ज्यादा है, दूसरी जगह कम है अब यह तो आप देखें कि कैसे एफिश्येंसी को ठीक करेंगे।

मैं आप का ध्यान जो मेमोरेंडम का रेलीवेंट पोर्शन है उसकी तरफ़ दिलाना चाहता

हूं। आप कहते हैं कि कोयले की क्वालिटी खराब है। मैंने जो एलीगेशंस लगाए थे कि उसमें पत्थर आते है, दूसरी एक्सट्रेनियस चीजें आती हैं, उसको रोकने के बारे में आपने क्या कदम उठाये हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। मेमोरेंडम में यह है :

> I am quoting from the Memorandum. "It is known that substantial quantities of Shale and stones had been piled at collieries prior to nationalisation. Since then at least 1,000 million tonnes of coal has been produced."

I want a confirmation whether it is correct or not. This is very important. I would like to read further.

> "Even allowing a conservative proportion of about 10 per cent stones and shales, another 100 million tonnes would have been added to the piles. It is also known that at present such piles have all out disappeared. Obviously bulk of this must have been despatched to power stations at an estimated direct cost to them of Rs. 3000 crores."

This is a serious situation.

जिसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया कि यह पत्थर, बोल्डर और दूसरी बड़ी बड़ी चीजें जो जाती हैं उससे मशीनरी डेस्ट्राय हुई है और पावर-हाउसेज की वर्किंग भी बन्द हुई है। आपने बताया कि एलाबोरेट मेजर्स लिए हैं लेकिन उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता है। जाने वाले पत्थरों को सभी देखते हैं। इसमें कहीं न कहीं पर कोई बड़ी गड़बड़ी है। तो कहीं इसके पीछे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट तो नहीं हैं— यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री दलबीर सिंह : कोई वेस्टेट इन्ट्रेस्ट होगा— ऐसा शक ख्वामख्वाह आप क्यों कर रहे हैं ? एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, पूरी कोशिश में है कि किसी तरह से इम्प्रूमेंट आए। उन्होंने जो कोशिश की है उससे प्लांट लोडिंग फैक्टर बढ़ा है। जहां तक कोयले का सवाल है, उसमें पत्थरों का सवाल है, हमने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को सुधारने के लिए काफी एटेम्प्स लिए हैं। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कोल हैंडलिंग प्लान्ट्स में ज्वाइन्ट सैम्पलिंग की व्यवस्था की गई है कि दोनों डिपार्टमेंट मिलकर देख लिया करें। अभी एक मीटिंग हुई, उसमें फैसला किया गया कि लोडिंग के प्वाइन्ट पर और आगे के प्वाइन्ट पर दोनों जगह ज्वाइन्ट सैम्पलिंग के जरिए से क्वालिटी को देख लें और अगर कोई दूसरा मैटीरिएल उसमें हो तो उसकी चांज कर लें। जांच करने के भी डिफ़रेंट तरीके हैं। कोल तरीके हैं। कोल हैंडलिंग प्लान्ट्स के जरिए क्वालिटी तो इम्प्रूव करने और एक्सट्रानिक्स मैटीरियल को निकालने की यह सारी बातें होती हैं।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : मेमोरेंडम के बारे में आपका क्या कमेंट है ? यह गलत है, सही है या एग्जाजरेटेड है— आपका क्या कहना है ?

श्री दलबीर सिंह : मेमोरेंडम इतने एलाबोरेट होते हैं कि बहुत सारी चीजों को कवर कर लेते हैं और वह सिर्फ एक डिपार्टमेंन्ट से ही ताल्लुक नहीं रखती हैं। बहुत से डिपार्टमेन्ट्स से उनका ताल्लुक रहता है। अगर मेमोरेंडम की बेसिस पर चलें तो पता नहीं कितने डिपार्टमेंट एक साथ आ जायेंगे। इसलिए जो भी बात रेलेवेन्ट है, जितना भी प्रोशन रेलेवेन्ट है उसको नोट करके एक तरीके से काम होता है। अगर सारे मेमोरेंडम पर मैं जाऊं तो यह एक बहुत बड़े डिस्कशन का मजबून बन जायेगा और

उसके एक आइटम में ही यह क्वेश्चन आवर खत्म हो जायेगा। इसलिए उसकी सारी चीजों को कवर करना मुमकिन नहीं होगा। रेलिवेन्ट बातों को ही नोट करके उन पर डिपार्टमेंट ऐक्शन लेता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वे कदम उठा रहे हैं। यह बात जरूर है कि वे कदम उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कदम बढ़ाने के साथ-साथ मशीनरी को भी तेज करें। मन्त्री जी बताने की मेहरबानी करें यह जो 57 परसेंट अभी बाकी है यह कब तक हो जायेगा।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि प्लान्ट्स को चलाने की पूरी जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर है या स्टेट गवर्नमेंट पर भी है ? अगर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और यह उनके कंट्रोल में हैं तो इस बारे में मन्त्री जी क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा है कि कब तक करेंगे। 47 परसेंट तो उन्होंने मान ही लिया है और जैसा मैंने पहले बतलाया है कि 1986-87 तक 88 परसेन्ट टोटल कोल प्रोडक्शन कोल हैंडलिंग प्लांट्स के अंतर्गत आ जायेगा।

जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, आप जानते ही हैं कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बने हुए हैं जोकि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स को जरा टच करो, जैसे साउथ की स्टेट्स हैं या वेस्ट बंगाल की स्टेट है उनको जरा सा भी टच कर दिया जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। पावर जनरेशन का सवाल आता है। इसके अन्दर भी कंसलटेटिव कमेटी है, जिसने यूरेनिमस राय दी थी कि किसी तरह से इसको सेन्ट्रल तरीके से इम्प्रूव किया जाए। उसके खिलाफ स्टेट्स के अंदर रियैक्शन इतना है कि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बहराल, इन्ट्रैक्शन्स बराबर दी जाती हैं। प्लांट लोड फैक्टर और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए इन्स्ट्रक्शन्स दी जाती हैं। बाई-एंड-लार्ज वे उन इन्स्ट्रक्शनस को मानते हैं।

SHRI A.K. Roy : What would the coal handling plant do if you are yourself a party *in sending stones and shales to the power* plants ? All that glitters is not gold and all that is black is not coal. But according to the theory of CIL anything that looks black is coal whether it is a stone, shale or even a human being. That is why the Energy Minister never visits coalfields. He is afraid that the coal-loaders may dump him one day and when the doors will be opened far flung, you will be surprised to see that the Minister is coming out of it.

SHRI P. SHIV SHANKAR : Thank you for the compliments.

SHRI A.K ROY : I would like to know two things. How many officers were brought to book for sending shales and stones to the power plants ? Is it a fact, as pointedly mentioned in the memorandum, that Rs. 3000 crores worth of stones were supplied in the name of coal ? It is a national crime. Have any officers been brought to book or not ? Is it a fact that previously shale pickers used to be there to separate coal and shales? You have eliminated those shale pickers and for that reason there is none to separate shales from coal and you are sending shales and stones to the power plants.

SHRI DALBIR SINGH : Regarding action to be taken against any officer for any violation, wherever there is any violation on the part of any officer, action is always taken. If he has something specific in his mind regarding supply of shales stones, etc. against any officer, he can give me so that I

can take action against that officer. (*Interruption*)

SHRI A.K. ROY : I am explaining. Whenever shales and stones are sent, deductions are made by the power plants, because they can catch immediately. How many deductions are made ? Some time back Badarpur power Station deducted 90 per cent of the price of coal. Who was made responsible for that ?

SHRI DALBIR SINGH : There is no point in getting agitated on this. (*Interruption*) The question is so simple, If there is any violation on the part of any officer, we can take action against him. Regarding quality, there is another question about the quality of coal. (*Interruption*)

MR. SPEAKER : Is there any specific allegation or truth that about Rs. 3000 crores worth of stones were supplied ?

SHRI DALBIR SINGH : That is not correct.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : We are discussing a very important subject and the two Ministers have pointed out that poor quality of coal, bad maintenance and all these things have contributed to the poor plant load factor. You must have noticed that both the Ministers have pointed out about the defective design of the boilers supplied by BHEL. I would like to know how is it that the same company, BHEL, supplying the same thing to Libya and Malaysia and the performance has been more or less hundred per cent ?

If the same design exported to Libya and Malaysia can function efficiently, I would like to know why the boiler, with same design and same technology, when supplied to India, cannot function. ? Is it because it is defective ? If it is defective, it is defective for Libya and Malaysia also. So, if this is not the reason, then what are the reasons for its not functioning efficiently ?

SHRI P. SHIV SHANKAR : Sir, on the direct question that has been posed by my hon. friend, I may submit that it is true that some of the boilers and the generators that have been supplied by the BHEL to the foreign countries, have been doing exceedingly well. In our country so far as coal is concerned, it varies from mine to mine. Its quality has been a bit different from mine to mine and as a results of this when the coal is supplied to a particular power plant and if that power plant is equipped with the boiler and the generator for a particular type or grade of coal, coal, then the difficulty will arise. As a result of this, the plant load factor has been affected.

When my colleague says that the plant load factor has been affected because of the quality of coal, the fact is that it is not only because of coal, other factors are also there. But I concede that the quality of coal deserves to be improved. Hon. Members have expressed time and again about the shells and stones, including me. I have no objection to that. Still my quality has also to improve. (*Interruption*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Black is always beautiful. I am proud of my black hair.

SHRI P. SHIV SHANKAR : Mr. Chakraborty, I must also take into consideration the observations of some other friends. So, the point is that constant efforts have to be made to improve the coal. Measures are being taken. but I do concede that they have not conformed to the level of expectation. If some of the officers have been responsible and if it has come to our notice, we have taken action ; it is not that we have not taken action. In recent times because of the mechanised open-cast mining the qality of coal has gone down. When the production was less, there used to be coal pickers but now it is not possible. In fact, recently I hvae introduced a system of joint sampling. Contracts are being entered into with all the Electricity Boards and they will pay the money according to the quality of the coal. If there are shells, etc.' they will not take it. In fact, various measures are already being taken and I assure the House that we will try to do our best to reach perfection as early as possible. But as on today, the state of affairs is known to the

House and I have also been trying to explain. Our endeavour has been to see that the quality of the coal improves. Constant measures have to be taken for this.

Investment in Hindustan Fertilizers, Haldia

*231. SHRI MANORANJAN BHAKTA : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) The total amount of investment made in Hindustan Fertilizers at Haldia with year-wise break-up and foreign exchange spent, ;

(b) when the plant was commissioned and if not, when it is likely to be commissioned ; and

(c) what will be the total production of ammonia vis-a-vis the installed capacity of the plant ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI R.C. RATH) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The total amount of investment made in Haldia Fertilizer Project of Hindustan Fertilizers Corporation Ltd. as on 30.6. 1984 is Rs. 332.72 crores as per details given below :—

(Rs. crores)

Amount of Investment

Year	Indian currency	Foreign currency	Total
1970-71	Nil	0.09	0.09
1971-72	0.57	2.08	2.65
1972-73	6.28	3.95	10.23
1973-74	9.18	4.61	13.79
1974-75	19.41	7.12	26.53
1975-76	38.04	9.41	47.45
1976-77	34.46	6.46	40.92
1977-78	35.72	2.60	38.32
1978-79	17.56	1.62	19.18
1979-80	21 66	0.82	22.48
1980-81	23.50	0.56	24.06
1981-82	20.62	0.48	21.10
1982-83	32.87	0.73	33 60
1983-84	26.95	0.47	27.42
1984-85 (Apr-June, 1984)	4.90	Nil	4.90
Total	291.72	41.00	332.72

(b) It has not been possible to commission the plant so far due to equipment failures. Commissioning activities of the ammonia plant are held up atpresent due to non-availability of the Oxygen compressors since end-1983 when two of the 3 Oxygen compressors were damaged by fire and the third compressor developed a crack. Urgent measures are being taken by HFC to repair the compressors and put then in line. As soon as this is done commissioning activities will be resumed.

(c) The installed capacity of the ammonia plant is 198,000 TPA. The quantity of ammonia which will be produced by the plant can be ascertained only after production has stabilised.

SHRI MANORANJAN BHAKTA : Sir, the statement given by the hon. Minister gives a grim picture. During the last fifteen years, more than Rs. 332 crores have been spent on Haldia fertilizer project and out of this amount, Rs. 41 crores have been spent in terms of foreign exchange, but even within these fifteen years, the plant could not be